

दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए  
संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ व्यापार घाटा

4948. श्री डी. एम. कथीर आनंद:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि विगत पांच वर्षों के दौरान निर्यात में गिरावट और आयात में वृद्धि होने के कारण अमेरिका और चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने चीन और अमेरिका के साथ भारत के व्यापार घाटे को संतुलित करने के लिए कोई उचित उपाय किए हैं;
- (ग) क्या सरकार की हमारे देश के आयात के लिए चीन पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, इज़राइल और जर्मनी जैसे अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) चीन और अन्य देशों के साथ व्यापार घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या सक्रिय कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ भारत का वस्तु व्यापार संतुलन (मिलियन अमेरिकी डॉलर में मूल्य) निम्नवत है: -

भारत का व्यापार संतुलन	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
यूएसए के साथ (आधिशेष)	17,268.90	22,735.05	32,852.94	27,678.73	35,319.54
चीन के साथ (घाटा)	-48,647.99	-44,025.10	-73,310.78	-83,199.66	-85,076.85

स्रोत: डीजीसीआईएस

(ख) से (घ):जहां तक यूएसए का संबंध है, भारत ने पण्यवस्तु व्यापार में अधिशेष बनाए रखा है। हालांकि, विशेष रूप से चीन के साथ समग्र व्यापार घाटे को दूर करने घरेलू आपूर्ति बढ़ाने, आयात पर निर्भरता को कम करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने कई पहल की हैं। 'मेक इन इंडिया'

पहल के अंतर्गत, सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, व्हाइट गुड्स, टेलीकॉम और नेटवर्किंग उत्पादों, उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल आदि जैसे 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन लिंक प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की हैं, जहां आयात पर अत्यधिक निर्भरता है। सरकार ने बाजार में आयातित उत्पादों सहित अवमानक और निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों की जांच करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, परीक्षण प्रोटोकॉल और अनिवार्य प्रमाणन के लिए सख्त गुणवत्ता मानक और उपाय लागू किए हैं। सरकार भारतीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं का पता करने और आपूर्ति के एकल स्रोतों पर निर्भरता को कम करने के लिए अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। सरकार नियमित आधार पर आयात में वृद्धि की निगरानी करती है और उचित कार्रवाई करती है। इसके अलावा, व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) को अनुचित व्यापार परिपाटियों के खिलाफ व्यापार उपचारात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने का अधिकार है। डीजीटीआर ने अप्रैल 2021 से दिसंबर 2024 तक चीन के विरुद्ध 129 व्यापार उपचार मामले शुरू किए हैं।

(ग): वर्तमान में, भारत यूरोपीय संघ (ईयू) और यूनाइटेड किंगडम (यूके) दोनों के साथ क्रमशः भारत-ईयू और भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए वार्ताएं कर रहा है। इन वार्ताओं का उद्देश्य निष्पक्ष, न्यायसंगत, पारस्परिक रूप से लाभकारी और व्यावसायिक रूप से सार्थक समझौतों को प्राप्त करना है। यूरोपीय संघ के संबंध में, जिसमें जर्मनी एक सदस्य है, जून 2022 में बातचीत फिर से शुरू होने के बाद से मार्च 2025 तक दस दौर की बातचीत हो चुकी है। भारत-यूके एफटीए के लिए बातचीत, जो शुरू में 13 जनवरी 2022 को शुरू की गई थी, मई 2022 में 14वें दौर के दौरान भारत और ब्रिटेन दोनों में चुनावों के कारण रोक दी गई थी। इसके बाद, दोनों प्रधानमंत्रियों ने नवंबर 2024 में रियो डी जनेरियो में जी-20 शिखर सम्मेलन के मौके पर मुलाकात की और बातचीत को फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। यूनाइटेड किंगडम के व्यवसाय और व्यापार विभाग के राज्य सचिव, माननीय जोनाथन रेनॉल्ड्स ने 24-25 फरवरी 2025 के दौरान नई दिल्ली का दौरा किया और वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के साथ संयुक्त रूप से 24 फरवरी 2025 को वार्ता की औपचारिक शुरुआत की घोषणा की। अभी तक, इजराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) विचाराधीन नहीं है। इसके अलावा, जहां तक अमेरिका का संबंध है, दोनों पक्षों ने हाल ही में पारस्परिक रूप से लाभकारी बहु-क्षेत्र द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत करने पर सहमति व्यक्त की है। इस पर भारत और अमेरिका के बीच चर्चा शुरू हो गई है।

\*\*\*\*\*